



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मई 2023 — ज्येष्ठ 10, शक 1945

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक F 10-9/2023/तक.शि./42. — जहां कहीं आधार का उपयोग एक परिचय पत्र अभिलेख के रूप में सेवाओं के वितरण प्रक्रिया या फायदे या अनुवृत्ति के लिए किया जाता है जो सरकार की वितरण प्रक्रिया को सरलीकृत करती है। पारदर्शिता और क्षमता को प्रदर्शित करती है और हितग्राहियों को उनकी पात्रता को प्रत्यक्ष रूप से आसान एवं सुविधापूर्वक निर्वाह रूप से प्रदान करने में परिचय पत्र के लिए सबूतों के रूप में लिये जाने वाले विविध अभिलेखों से छुटकारा दिलाता है।

और जहां, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर द्वारा आयोजित भर्ती, प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। परीक्षा शुल्क मुक्त हो जाने से अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जा रहा है जिससे आवेदनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तथा सार्वजनिक निधियों का अपव्यय हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल का निर्माण छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, (चिप्स) स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) द्वारा तैयार एवं विकसित किया गया है।

और जहां, अभ्यर्थियों का आधार अधिप्रमाणन एवं e-KYC हो जाने से सार्वजनिक निधियों के अपव्यय को रोका जा सकता है। साथ ही लाभार्थी अपने सत्यापित जानकारी के माध्यम से त्रुटि रहित प्रवेश, पात्रता एवं भर्ती परीक्षाओं में बगैर शुल्क दिये भाग ले सकता है।

और जहां उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन में समेकित निधि आवर्ती से व्यय होता है।

अतः इसलिए आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ) एवं सेवा का अधिनियम, 2016 की धारा-7 का उपयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन इस प्रकार निम्नानुसार अधिसूचित करता है। अर्थात् :-

- (1) कोई भी निवासी व्यक्ति जो उक्त योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे आधार क्रमांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।
- (2) कोई भी निवासी व्यक्ति जो योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है और जिसके पास आधार क्रमांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है को अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति पर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा (बाल लाभार्थियों का मामले में) बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की वेबसाइट www.uidai.gov. पद पर जाकर आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम-12 के अनुसार विभाग को अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन हितग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और आधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित नामांकन केंद्र, नहीं होने पर विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर दिया जाएगा। अर्थात् :-

(अ) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ब) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अर्थात् :-

- (i) बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक; या
- (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) राशन कार्ड; या
- (v) मतदाता पहचान पत्र; या
- (vi) मनरेगा कार्ड; या
- (vii) किसान फोटो पासबुक; या
- (viii) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या
- (ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाण पत्र; या
- (x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नामित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितग्राहियों को योजनान्तर्गत आधार की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात् :-

- (अ) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस प्रमाणीकरण की सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस प्रमाणीकरण के साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रूप से लाभ दिया जा सके।
- (ब) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरणसफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय बद्धता के साथ टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य होगा।
- (स) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसका प्रमाणीकरण आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पॉन्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है। क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी (बच्चों के अतिरिक्त) मिलने वाले लानों से वंचित न हो, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेंगे जैसा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में निर्दिष्ट है (<https://dbtbharat.gov.in/> पर उपलब्ध)
5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 30th May 2023

NOTIFICATION

No. F 10-9/2023/T.E./42. — Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the local resident participants of Chhattisgarh appearing in the recruitment, entrance and eligibility tests conducted by the Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur under the Department of Skill Development, Technical Education and Employment, Government of Chhattisgarh have been exempted from examination fee. Since no fee is charged candidate fills more than one application which causes an unexpected increase in the number of applications and wastage of public funds. The portal for online application has been created and developed by Chhattisgarh Infotech Promotion Society, (CHIPS) State Data Center, Civil Line, Raipur (Chhattisgarh).

And whereas, Aadhaar authentication and identification of candidates can prevent wastage of public funds. Along with this, the beneficiary can take part in error-free admission, eligibility and recruitment examinations without paying any fee through his verified information.

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Chhattisgarh State;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (here in after referred to as the said Act), the Government of Chhattisgarh here by notifies the following, namely:-

1. (1) An individual who desires to avail the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals subject to production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely:-
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identity Card; or
 - (vi) MGNREGA card; or
 - (vii) Kisan Photo passbook; or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
 - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
 - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbt Bharat.gov.in/>).
5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.